of functioning;

(d) what was the overall performance made by the Navodaya Vidyalayas in Gujarat during the years 1992-93 and 1993-94; and

(e) if not, the measures proposed to be taken by Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (KUMARI SELJA): (a) and (b) The Navodaya Vidyalaya scheme has the objective of setting up one Navodaya Vidyalaya in a district to provide good quality education to the talented children predominantly from the rural areas. In these schools at least 75% seats are earmarked for children from rural areas. Reservation for SC/ST is in proportion to their population in the district, subject atleast to nationally prescribed percentage. Attempt is made to enrol about 30% girls. The Navodaya Vidyalaya Samiti is continuously making efforts to realise the aims and objectives of the scheme.

(c) The Council and the Executive Committee constituted in accordance with the Memorandum of Association and Rules of the Navodaya Vidyalaya Samiti supervise the working of the Samiti, including the Navodaya Vidyalayas.

(d) A Statement is annexed (*see* below).

(e) Does not arise.

Statement

OVER-ALL PERFORMANCE OF NAVODAYA VIDYALAYAS IN GUJARAT.

Academic Results:

CLASS X

Year	No. of JNVs	No. Appeared	No. Passed	Pass %age
1992-93	06	250	242	95.8%
1993-94	07	316	297	93.98%

CLASS XII

Year	No. of JNVs	No. Appeared	No. Passed	Pass %age
1992-93	02	77	50	64.9%
1993-94	07	149	89	59.73%

Primary Schools in the Country

2510. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that even today more than 35% of our primary schools do not have Black-Boards after the Operation Black Board was launched in 1987-88; and

(b) if so, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (KUMARI SELJA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

महाराष्ट्र के कोंकण जिले के लिए विश्वविद्यालय

2511. श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य में चल रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में दो-दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और कुछ राज्यों में एक भी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस असंतुलन को दूर करने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र में सागर विकास और मत्स्य पालन से संबंधित कोई विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) इस समय 12 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों की राज्य-वार सूची संलग्न है। (नीचे देखिए)।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च): केन्द्रीय विश्वविद्यालय विशिष्ट शैक्षिक एवं केन्द्र राज्य दृष्टिकोणों को देखते हुए स्थापित किए जाते हैं। ये राज्य-वार स्थापित नहीं किए जाते।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 तथा कार्रवाई योजना 1992 में शिक्षा के समेकन पर बल दिया गया है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी सिफारिश की है कि संसाधनों की अत्यधिक कमी के कारण, सरकार को नए विश्वविद्यालय स्थापित करने पर नियंत्रण लगाना चाहिए।

सूची

देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम

क्रम सं.	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना का वर्ष
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद विश्वविद्यालय	1974
2.	असम	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	1994
		तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	1994
3.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	1922
		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	1985
		जामिया मिलिया इस्लामिया	1989
		जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1969
4.	मेघालय	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	1973
5.	पांडिचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	1985
6.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1920
		बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1916
7.	पश्चिम बंगाल	विश्व-भारती	1951

गुजरात स्थित विश्वविद्यालयों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान

2512. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गुजरात स्थित विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या राज्य के सभी विश्वविद्यलायों ने अनुदान सहायता की पूरी राशि का उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी विश्वविद्यालय ने अप्रयुक्त अनुदान राशि को वापस लौटाया है;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा गुजरात को वित्तीय आवंटन के संबंध में किसी नई योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप–मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, पात्र विश्वविद्यालयों को अनुदान पंच वर्षीय योजनावधि के लिए आवंटित किए जाते हैं न कि वार्षिक आधार पर आठवीं योजना के लिए गुजरात में विभिन्न विश्वविद्यालयों को आवंटित किए गए अनुदान तथा 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)।

(ख) पात्र विश्वविद्यालयों को आवंटित किए गए अनुदान उनके द्वारा मार्च, 1997 तक उपयोग किए जा सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विषयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए गुजरात के निम्नलिखित संस्थानों के प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं।